

## Import items must be given importance

AGE CORRESPONDENT  
NEW DELHI, MARCH 5

For success of its flagship programme Make in India, the Centre should first target high import intensive items like electronic goods, machinery, steel and transport equipment, said Assocham.

It said that import in these sectors add close to \$9 billion or over 27 per cent of the country's monthly import bill.

"There are other major import items like crude oil, gold and precious stones which cannot be produced indigenously or are used for re-exports. But a growing economy like India which is witnessing a huge expansion in usage of telecom and other items using electronics, should go about in a focused manner to

drastically cut imports of the items which can be substituted by domestic production and add to the country's manufacturing strength. This is eminently doable, provided the policy initiatives are put in place and implemented with great clarity and speed both by the Centre and the states," it said.

It said that the latest figures show import of close to \$4 billion for electronics, \$2.36 billion for electrical and non-electrical machinery, \$1.47 billion for transport equipment and about \$1 billion for iron and steel.

Thanks to demand for user industries particularly telecom, automobile, smart consumer devices, the annualised imports of electronics goods grew at a 24.56 per cent in January, 2017, said Assocham.

## एसोचैम रिपोर्ट... मेक इन इंडिया में बाधक है आयात पर अधिक निर्भरता

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. उद्योग संगठन एसोचैम ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद के साथ शुरू की गई सरकारी पहल 'मेक इन इंडिया' की सफलता के लिए इलेक्ट्रॉनिक और परिवहन उपकरणों जैसे आयात निर्भर उत्पादों को बाधक बताते हुए कहा है कि इन उत्पादों के आयात पर हर माह भारी संख्या में विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल होता है।

रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मशीनरी, स्टील और परिवहन उपकरणों को भारी मात्रा में आयात किया जाता है और इन उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली राशि देश के कुल मासिक आयात व्यय का 27 फीसदी हिस्सा है, जो करीब नौ अरब डॉलर है। आंकड़ों के अनुसार देश में करीब चार अरब डॉलर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, 2.36 अरब डॉलर इलेक्ट्रिक तथा नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी, 1.47 अरब डॉलर परिवहन उपकरण और लगभग एक अरब डॉलर लोहे एवं स्टील के आयात पर खर्च किए जाते हैं। इन सामानों के अलावा अन्य उत्पाद भी आयात किए जाते हैं जैसे कच्चा तेल, सोना और बहुमूल्य रत्न।



# 'मेक इन इंडिया की सफलता में बाधक हैं आयात निर्भर उत्पाद'

## देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पर 2.36 अरब डॉलर व नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी, 1.47 अरब डॉलर होता है खर्च

नई दिल्ली, 5 मार्च (एजेंसियां)। उद्योग संगठन एसोचैम ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद के साथ शुरू की गई सरकारी पहल 'मेक इन इंडिया' की सफलता के लिए इलेक्ट्रॉनिक और परिवहन उपकरणों जैसे आयात निर्भर उत्पादों को बाधक बताते हुए कहा है कि इन उत्पादों के आयात पर हर माह भारी संख्या में विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल होता है। एसोचैम की आज जारी विश्लेषण रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मशीनरी, स्टील और परिवहन उपकरणों को भारी मात्रा में आयात किया जाता है और इन उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली राशि देश के कुल मासिक आयात व्यय का 27 फीसदी हिस्सा है, जो करीब नौ अरब डॉलर की है और यह निस्संदेह बहुत बड़ी राशि है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में करीब चार अरब डॉलर इलेक्ट्रॉनिक



इन उत्पादों के आयात पर हर माह भारी संख्या में विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल होता है। इन उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली राशि देश के कुल मासिक आयात व्यय का 27 फीसदी हिस्सा है: एसोचैम

उत्पाद, 2.36 अरब डॉलर इलेक्ट्रिक तथा नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी, 1.47 अरब डॉलर परिवहन उपकरण और लगातार एक अरब डॉलर लोहे एवं स्टील के आयात पर खर्च किये जाते हैं। एसोचैम के अनुसार इन सामानों के अलावा अन्य उत्पाद भी आयात किये जाते हैं जैसे कच्चा तेल, सोना और बहुमूल्य रत्न। इन उत्पादों का देश में उत्पादन नहीं किया जा सकता है और इनका आयात ज्यादातर किसी अन्य देश को दोबारा निर्यात करने के

लिए किया जाता है। दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और स्मार्ट कंज्यूमर डिवाइस की बढ़ती मांग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामानों का वार्षिक आयात गत जनवरी में 24.56 फीसदी बढ़ गया। देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को इस्तेमाल करने वाले क्षेत्र जैसे दूरसंचार आदि का तेजी से कारोबार विस्तार हो रहा है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को इस मौके का लाभ उठाते हुए उन उत्पादों के आयात को तेजी से कम करने पर ध्यान देना

चाहिए, जो देश में बनाए जा सकते हैं और इसका एक लाभ यह भी है कि इससे देश की विनिर्माण शक्ति बढ़ेगी। एसोचैम का कहना है कि ऐसा आसानी से किया जा सकता है अगर इस दिशा में नीतिगत पहल की जाए और उसे पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाए। उद्योग संगठन के महासचिव डॉ एस रावत के अनुसार मेक इन इंडिया की सफलता के लिए सरकार को पहले इन आयात निर्भर उत्पादों की ओर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी उस उत्पाद का, जो देश में निर्मित किये जा सकते हैं, उनका भारी मात्रा में आयात मेक इन इंडिया पहल के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। उनका कहना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन चुनिंदा उत्पादों का निर्माण भारत निवेशकों या विदेशी निवेशकों के

जरिये देश में ही हो। इसके अलावा कर का ढांचा भी ऐसा तैयार करना चाहिए कि भारत विनिर्माण इकाइयां आयातित उत्पादों से टकरा ले सकें। रावत ने कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने का अन्य लाभ यह है कि इससे भारी संख्या में रोजगार सृजन होगा। देश के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां नया निवेश मुश्किल साबित हो रहा है, वहां इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा क्षेत्र है, जहां देश के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है और इतना बड़ा क्षेत्र आयात निर्भर है। इस कारण इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। कर्नाटक जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाये हैं लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इसी तरह परिवहन उपकरणों में भी निवेश को आवश्यकता है और स्टील निर्माताओं को भी कुछ खूट देनी चाहिए।